

# न्यूज़ टुडे

## सरकार ने संशोधित शक्ति (SHAKTI) नीति को मंजूरी दी

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए संशोधित शक्ति/ SHAKTI नीति को अनुमोदित किया।

- **शक्ति/ SHAKTI:** भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन व आवंटन करने की योजना।
- इसे 2017 में कोयला मंत्रालय ने शुरू किया था। यह विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटित करने का एक पारदर्शी तरीका है।

संशोधित शक्ति नीति की मुख्य विशेषताएं

- **उद्देश्य:** यह आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देगी और विद्युत क्षेत्र की कोयला मांगों को पूरा करने के लिए आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करेगी।
- **सरलीकृत आवंटन ढांचा:** यह विद्युत क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए पहले की 8 श्रेणियों को 2 सरलीकृत तलों में समेकित करके कोयला आवंटन को सुव्यवस्थित करेगी।
  - ⊕ **विंडो-I:** केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले ताप विद्युत संयंत्रों (जिनमें उनके संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियां भी शामिल हैं) को अधिसूचित कीमतों पर कोयला लिंकेज प्रदान किया जाना जारी रहेगा।
  - ⊕ **विंडो-II:** घरेलू या आयातित कोयले का उपयोग करने वाले उत्पादकों सहित सभी ताप विद्युत उत्पादक अब अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम का भुगतान करके नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कोयला खरीद सकते हैं।
- **अनिवार्य PPAs (पावर परचेज एग्रीमेंट) को समाप्त करना:** विंडो-II के लिए, PPA की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
- **विद्युत क्षेत्र की गतिशील कोयला मांगों को पूरा करना:** नीलामी में 12 महीनों से लेकर 25 साल तक की अवधि के लिए खरीद की अनुमति होगी।
- **‘पिटहेड’ विद्युत संयंत्रों को प्राथमिकता:** यह नीति, ब्राउनफील्ड विस्तार का समर्थन करने के अलावा, मुख्य रूप से पिटहेड स्थलों पर यानी कोयला स्रोत के नजदीक ग्रीनफील्ड थर्मल पावर परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देगी।

कोयला क्षेत्र में किए गए अन्य प्रमुख सुधार

- **कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015:** इसके अंतर्गत पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाया गया है, परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई आदि।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021:** कम्पोजिट प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस-कम-माइनिंग लीज (PL-cum-ML) की शुरुआत की गई।
- **वाणिज्यिक कोयला खनन (2020):** निजी कंपनियों को अंतिम उपयोग प्रतिबंध के बिना वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोयला खनन की अनुमति दी गई है।
- **कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (CMSMS) तथा खनन प्रहरी ऐप:** अवैध कोयला खनन की घटनाओं पर मजबूती से निगरानी करने के लिए।

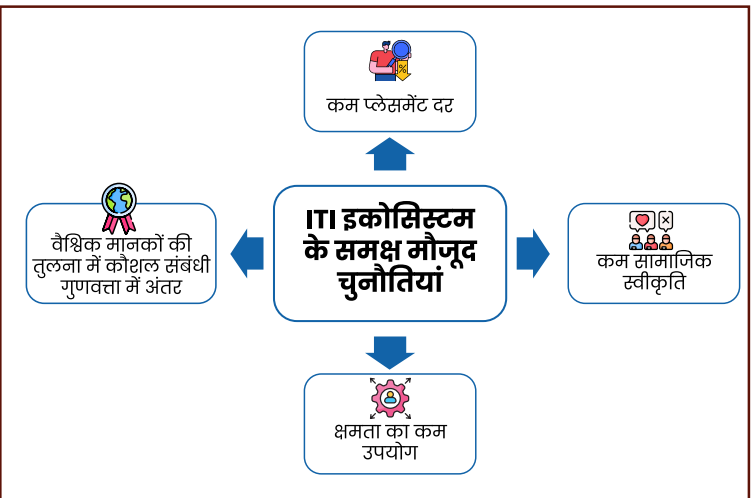
## कैबिनेट ने “औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के उन्नयन और कौशल विकास हेतु पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना” को मंजूरी दी

बजट 2024-25 के तहत घोषित इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। योजना के बारे में

- **उद्देश्य:** राज्य सरकारों और उद्योग जगत के सहयोग से, मौजूदा ITIs को सरकारी स्वामित्व वाले, उद्योग जगत प्रबंधित कौशल के आकांक्षी संस्थान के रूप में स्थापित करना है।
- **कुल परिव्यय:** इस योजना के तहत पांच वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्रीय हिस्सेदारी: 30,000 करोड़ रुपये, राज्यों की हिस्सेदारी: 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग जगत का खर्च: 10,000 करोड़ रुपये शामिल है।
  - ⊕ एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा समान रूप से केंद्रीय हिस्से के 50% की सीमा तक का सह-वित्तपोषण किया जाएगा।
- **फोकस**
  - ⊕ यह योजना उद्योग जगत के अनुरूप फिर से तैयार किए गए रुझानों (पाठ्यक्रमों) के साथ हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 1,000 सरकारी ITIs का उन्नयन करेगी।
  - ⊕ साथ ही, 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) की क्षमता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें इन संस्थानों में कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना भी शामिल है।
  - ⊕ परिणाम-आधारित कार्यान्वयन रणनीति के लिए उद्योग के नेतृत्व वाले स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) मॉडल को अपनाना।

ITIs के बारे में

- **संरचना:** राज्य सरकारों के अधीन संचालित, ITIs 1950 के दशक से भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) की नींव रहे हैं।
- **ITI की मान्यता:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) वास्तव में भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) के लिए सर्वोच्च संगठन है।
- **स्थिति:** वर्तमान में, लगभग 15,034 ITIs संचालित हैं। इनमें से 78% निजी स्वामित्व वाले हैं।
- **योजनाएं:** औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव/ STRIVE), मॉडल ITI, पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास अवसंरचना को बढ़ाना (ESDI)।



## लद्दाख के वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा किए गए अध्ययन में लद्दाख में 477 हिम तेंदुए होने का अनुमान लगाया गया

दुनिया में हिम तेंदुओं का सर्वाधिक घनत्व लद्दाख में है, जो भारत की कुल हिम तेंदुआ आबादी का 68% हिस्सा है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **क्षेत्र:** हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह में हिम तेंदुओं का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व पाया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सन्निकित (Contiguous) आबादी में से एक है।
- **उच्च घनत्व के लिए कारक:**
  - ⊕ संसाधनों से भरपूर घास के मैदान, अनुकूल जलवायु और शिकार की प्रचुरता।
  - ⊕ सीमित मानवीय व्यवधान यानी लद्दाख में 61% हिम तेंदुए मानव आबादी के साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं।
  - ⊕ लद्दाख की जनजातियों में वन्यजीवों के प्रति सांस्कृतिक सम्मान, हिम तेंदुआ पर्यटन से होने वाला आर्थिक लाभ और संघर्ष प्रबंधन की रणनीतियां आदि अन्य जिम्मेदार कारक हैं।

हिम तेंदुए (पेंथेरा अन्सिया) के बारे में

- **भौगोलिक विस्तार:** यह दक्षिण और मध्य एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों की प्रमुख प्रजाति है। यह 12 देशों में पाया जाता है।
  - ⊕ भारत में, पश्चिमी हिमालय में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम तथा पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - ⊕ IUCN रेड लिस्ट: वल्नरेबल।
  - ⊕ CITES परिशिष्ट-I और CMS परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध।
  - ⊕ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध।
- **पर्यावास:** हिम तेंदुआ 3,000-5,000 मीटर की ऊँचाई पर चट्टानी व पथरीली तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि पर रहता है।
- **विशेषताएं:** हिम तेंदुए के शरीर पर स्मोकी धूसर (ग्रे) रंग के फर होते हैं, जिस पर काले-गहरे धूसर रोसेट (गोलाकार धब्बे) होते हैं। वे अकेले रहते हैं तथा सुबह और शाम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।

## हिम तेंदुआ संरक्षण पहलें



भारत में हिम तेंदुआ परियोजना

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस

ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम

बिश्केक घोषणा-पत्र 2017 और समरकंद संकल्प 2024

## भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया

पहलगाव में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया। भारत की यह जवाबी कार्रवाई बालाकोट के बाद सबसे बड़ी सीमा-पार कार्रवाई मानी जा रही है।

- भारत ने आत्मरक्षा, भविष्य की आतंकी घटनाओं को रोकने और आतंकवाद को कठोर संदेश देने के अपने अधिकार का हवाला देते हुए यह ऑपरेशन शुरू किया है।

ऑपरेशन सिंदूर के बारे में

- यह पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया एक बड़ा सैन्य अभियान है।
- भारत की यह कार्रवाई सीमित, संतुलित और उकसावे से बचने वाली थी। इस ऑपरेशन में भारतीय रक्षा बलों ने अत्याधुनिक तकनीकी हथियारों का प्रयोग किया जो सटीक हमलों में सक्षम हैं।

- भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सटीक हमले करने वाले भारत के हथियार

- **SCALP (स्टॉर्म शीडो) मिसाइल:** यह 450 किलोमीटर की रेंज वाली एयर-लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसे दुश्मन देश के अधिक भीतर जाकर उच्च महत्व वाले लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **HAMMER (हाइली एंजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज):** यह 50-70 किलोमीटर की रेंज वाला प्रीसिशन-गाइडेड स्टैंड-ऑफ हथियार है।
- **लोइटर्ग म्यूनिशन (कामिकेज ड्रोन):** ये ड्रोन लक्षित क्षेत्र में मंडरते हैं और स्वतः या रिमोट-कंट्रोल से खतरे की पहचान कर उसे नष्ट करते हैं।
- **मेटियोर (METEOR) मिसाइल:** यह अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) एयर-टू-एयर मिसाइल है, जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्थितियों में भी प्रभावी है।
- **ब्रह्मोस मिसाइल:** यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'फायर एंड फॉरगेट (दागो और भूल जाओ)' सिद्धांत पर कार्य करती है।

### संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद-51

- इस अनुच्छेद के अनुसार किसी सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति में उसके व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार को संयुक्त राष्ट्र चार्टर नहीं रोकता।
- यह सुरक्षा परिषद को आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने हेतु कदम उठाने का आह्वान करता है।
- सदस्य देशों द्वारा आत्मरक्षा के उद्देश्य से की गई कार्रवाई की जानकारी तुरंत सुरक्षा परिषद को देना अनिवार्य है।

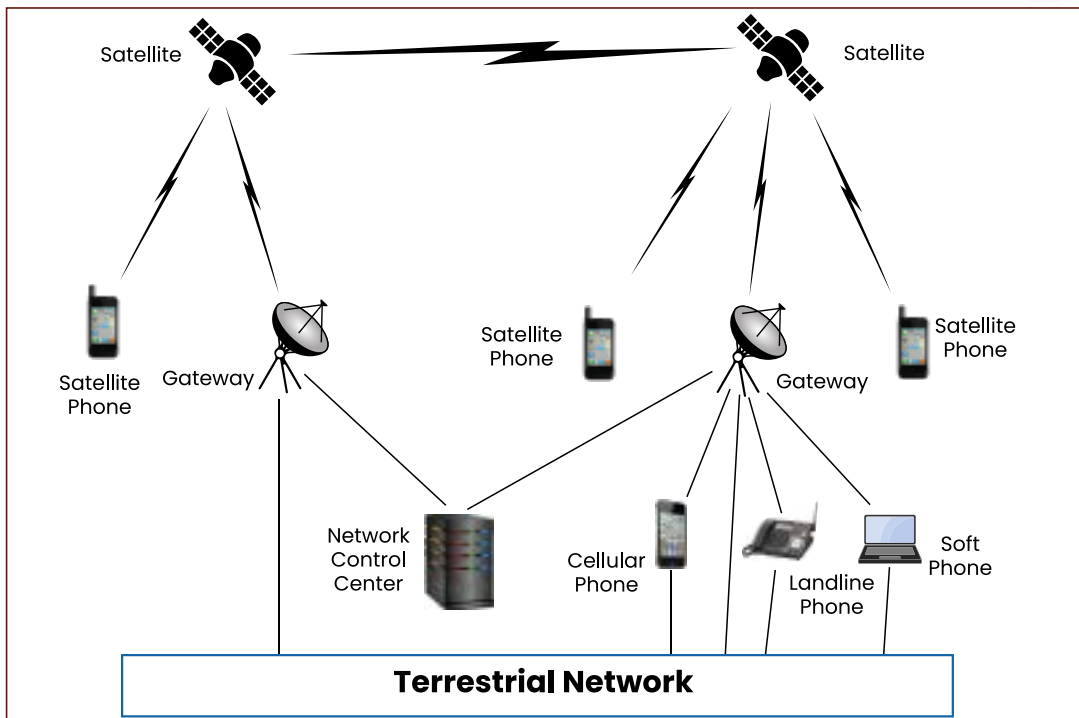
## दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा निर्देश जारी किए

ये निर्देश यूनिफाइड लाइसेंस (UL) समझौते के अंतर्गत ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) सेवा के लिए जारी किए गए हैं।

- GMPCS लाइसेंस यूजर्स के लिए उपग्रहों के माध्यम से मोबाइल संचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग खासतौर पर उन इलाकों में किया जा सकता है, जहां भूमि पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है।
- इस सेवा का उपयोग विशेष रूप से दूरस्थ खनन, तेल और गैस क्षेत्रों तथा सैन्य एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किया जाता है।

### मुख्य सुरक्षा निर्देश

- सुरक्षा मंजूरी: लाइसेंसधारी को भारत के भीतर प्रत्येक गेटवे या हब स्पेस के लिए सुरक्षा मंजूरी लेना जरूरी है।
- स्थानीयकरण: नेटवर्क कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर की जरूरी सुविधाएं (जैसे वैध अवरोधन सुविधा, यूजर डेटा ट्रैफिक रूटिंग आदि) भारत में ही स्थित होनी चाहिए।
- प्रतिबंध: लाइसेंसधारी को अधिकार दिया गया है कि वह युद्ध या तनाव की स्थिति में किसी भी ग्राहक या भौगोलिक क्षेत्र में सेवा को बंद या प्रतिबंधित कर सकता है।
- विशेष निगरानी क्षेत्र (SMZs): अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के भीतर के क्षेत्रों और 200 समुद्री मील तक के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को निगरानी के लिए SMZs घोषित किया जाएगा।
- अनिवार्य स्वदेशी विनिर्माण: सैटेलाइट नेटवर्क के ग्राउंड सेगमेंट का कम-से-कम 20% हिस्सा पांच साल के भीतर भारत में ही निर्मित होना चाहिए।
- NavIC/ नाविक पोजिशनिंग सिस्टम प्रावधान: लाइसेंसधारी NavIC-आधारित पोजिशनिंग का प्रावधान सुनिश्चित कर सकते हैं।



## अन्य सुर्खियां



### पुलित्जर पुरस्कार

2024 में पलकारिता के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने चार पुलित्जर पुरस्कार और द न्यू यॉर्कर ने तीन पुरस्कार जीते। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में

- यह पुरस्कारों का एक प्रतिष्ठित समूह है। पुलित्जर पुरस्कार हर साल न्यूयॉर्क शहर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है।
- इसकी शुरुआत जोसेफ पुलित्जर ने की थी, जो एक हंगेरियन-अमेरिकन पत्रकार और समाचार प्रकाशक थे। उनकी मृत्यु के बाद 1911 में उनकी संपत्ति का एक हिस्सा कोलंबिया यूनिवर्सिटी को दे दिया गया था।
- यह पुरस्कार पलकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।
- इसे पहली बार 1917 में प्रदान किया गया था।



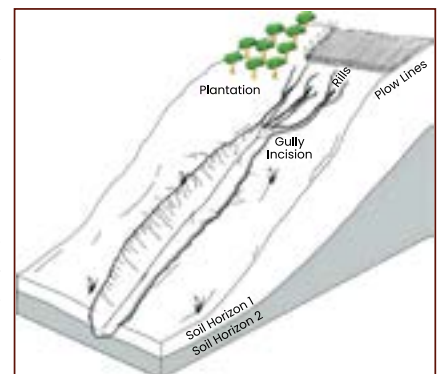
### अवनालिका अपरदन (Gully Erosion)

एक हालिया अध्ययन में 19 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवनालिका अपरदन से बनी स्थलाकृतियों को रेखांकित किया गया।

- भारत में अवनालिका अपरदन से प्रभावित 92% क्षेत्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ में हैं। इन राज्यों का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 38% है।

अवनालिका अपरदन के बारे में

- तेजी से बहता हुआ जल मृदा में कटाव करती हुई वाहिकाएं (चैनल) बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएँ कहते हैं। इनका विस्तार होता रहता है।
- इसके प्रभावों में शामिल हैं- भूमि, वनस्पतियों और फसलों को सीधा नुकसान पहुंचना; जलग्रहण क्षेत्र (वाटरशेड एरिया) के जल-अपवाह में परिवर्तन, भू-निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण।





## भारत का जलवायु वित्त-पोषण वर्गीकरण ड्राफ्ट फ्रेमवर्क (Draft framework India's Climate Finance Taxonomy)

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने “भारत का जलवायु वित्त-पोषण वर्गीकरण” का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी करके जनता से सुझाव मांगे हैं।

भारत के जलवायु वित्त-पोषण वर्गीकरण के बारे में

- यह वर्गीकरण एक प्रकार का उपाय या साधन है। यह उन गतिविधियों की पहचान करने में मदद करेगा, जो भारत के जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा उद्योग जगत और अर्थव्यवस्था को जलवायु अनुकूल बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
- मुख्य उद्देश्य:
  - जलवायु परिवर्तन शमन (Mitigation), अनुकूलन (Adaptation) और ट्रांजीशन में सहायता के जरिए पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों एवं गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु संसाधनों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना।
  - ग्रीनवॉशिंग यानी पर्यावरण अनुकूल होने के झूठे या भ्रामक दावों को रोकना।
- आधारभूत सिद्धांत (8 सिद्धांतों पर आधारित):
  - जलवायु कार्रवाई पर भारत की घोषित स्थिति और विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप;
  - ट्रांजीशन यानी जलवायु अनुकूल गतिविधियों का समर्थन करना,
  - स्वदेशी तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना आदि।



## तांबा (Copper)

अर्जेंटीना के फिलो डेल सोल और जोसेमारिया में तांबे के बड़े भंडार का पता चला है। इससे यह देश दुनिया की शीर्ष दस तांबा उत्पादक खानों में शामिल हो गया है।

तांबे (Copper) के बारे में

- तांबा नरम, आकृति में ढालने योग्य (malleable) और तन्य (ductile) धातु है। इसमें अत्यधिक तापीय और विद्युत चालकता होती है।
- विश्व में तांबे के बड़े उत्पादक देश (2024): चिली विश्व में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो, पेरू और चीन का स्थान है।
- भारत में तांबे के सबसे अधिक भंडार वाले राज्य: राजस्थान (52%), मध्य प्रदेश (23%) और झारखंड (15%) हैं।
- भारत में तांबे की मुख्य खानें:
  - सिंहभूम तांबा पट्टी: झारखण्ड;
  - खेतड़ी तांबा पट्टी – राजस्थान;
  - बालाघाट जिला – मध्य प्रदेश आदि।



## एटमोस्फियरिक मेमोरी

एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि मानसून का आगमन और वापसी केवल सूर्य के प्रकाश पर नहीं, बल्कि एटमोस्फियरिक मेमोरी पर भी निर्भर करती है

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वायुमंडल जलवाष्प के रूप में भौतिक जानकारी को संचित करता है। इस जानकारी के आधार पर यह मानसून के आगमन और वापसी को नियंत्रित करता है।
  - पहले यह माना जाता था कि मानसून मौसम के आगमन या वापसी की प्रक्रिया मुख्यतः सौर विकिरण (solar radiation) में परिवर्तन की तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है।
- नया सिद्धांत: वायुमंडल की स्थिति उसके मौसम के इतिहास पर निर्भर करती है। यदि पहले से वर्षा हो रही है, तो वह जारी रहती है, लेकिन यदि वातावरण पहले से शुष्क है, तो वर्षा की शुरुआत कठिन हो जाती है। यह व्यवहार “द्विस्थिरता” (Bistability) कहलाता है।
- समान सौर विकिरण स्तर पर भी वायुमंडल या तो शुष्क या गहन वर्षा वाला हो सकता है, हालांकि यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि पहले के मौसम की स्थिति क्या थी।



## गट माइक्रोबायोटा

एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाली खाद्य कमी और कुपोषण मानव आंत में मौजूद सूक्ष्मजीवों (गट माइक्रोबायोटा) की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- उत्पादकता में कमी: खाद्य उपलब्धता में कमी से लोगों को सही पोषण नहीं मिल पाता, जिससे आंत के माइक्रोबायल (सूक्ष्मजीवों) की विविधता घटती है।
- पोषण की गुणवत्ता में गिरावट: वायुमंडल में CO<sub>2</sub> के बढ़ने से चावल और गेहूं जैसी फसलों में आयरन, जिंक, पोटेशियम एवं प्रोटीन जैसे पोषक तत्व कम हो जाते हैं।

गट माइक्रोबायोटा

- मानव आंत में लगभग 100 ट्रिलियन सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं।
- असंतुलन और रोग: इन सूक्ष्मजीवों का असंतुलन डायबिटीज, आंतों की बीमारियों (IBD), एक्जिमा और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जुड़ा हुआ है।
- मिश्रित प्रभाव: आंत केवल भोजन की कमी से प्रभावित नहीं होती, बल्कि गर्मी, प्रदूषण और संक्रमण भी मिलकर असर डालते हैं।



## IMDEX एशिया

भारतीय नौसेना का पोत INS किल्टन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी (IMDEX) एशिया 2025 के 14वें संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा।

IMDEX एशिया के बारे में

- यह एशिया का अग्रणी नौसेना और समुद्री रक्षा कार्यक्रम है।
- उत्पत्ति: 1997 में।
- आयोजक: सिंगापुर गणराज्य की नौसेना।
- भागीदारी: 70 से अधिक देश।



## आयुर्वेदिक पांडुलिपियां

केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों- द्रव्यरत्नाकरनिघण्टु और द्रव्यनामाकरनिघण्टु को पुनर्जीवित किया है।

- आयुर्वेद में निघण्टु शब्द का तात्पर्य औषधियों के समूह, समानार्थक शब्द, गुण और उनके उपयोग किए जाने वाले भाग के विवरण से है।

द्रव्यरत्नाकर निघण्टु के बारे में

- लेखक: इसकी रचना 1480 ई. में मुदगल पंडित ने की थी।
- इसमें 18 अध्याय हैं, जो औषधि के पर्यायवाची, चिकित्सीय क्रियाओं और औषधीय गुणों पर गहन ज्ञान प्रदान करते हैं।
- यह ग्रंथ धन्वंतरि और राजा निघण्टु जैसे पुराने ग्रंथों पर आधारित है। हालांकि, इसमें पौधों, खनिजों और पशु स्रोतों से प्राप्त नई औषधियों का भी वर्णन मिलता है।

द्रव्यनामाकरनिघण्टु के बारे में

- लेखक: भीष्म वैद्य।
- यह ग्रंथ विशेष रूप से औषधियों और पौधों के नामों के समानार्थी शब्दों पर केंद्रित है, जो आयुर्वेद का एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण विषय है।
- यह धन्वंतरि निघण्टु का एक स्वतंत्र परिशिष्ट माना जाता है।



## इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (IPLN)

क्वाड के सदस्य देशों ने हवाई द्वीप के होनोलूलू में इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क सिमुलेशन पूरा किया।

- क्वाड के सदस्य हैं- ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका।

इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (IPLN) के बारे में

- यह पहल क्वाड देशों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा लॉजिस्टिक क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। इससे प्राकृतिक आपदाओं के समय नागरिक सहायता तेजी से और प्रभावी तरीके से प्रदान की जा सकेगी।
- यह नेटवर्क इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के साथ मिलकर, एक स्वतंत्र और मुक्त हिन्द-प्रशांत सुनिश्चित करने की क्वाड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, यह क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक सहयोग को सशक्त करने के महत्त्व को भी रेखांकित करता है।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



रांची



सीकर